भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

29.07.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1646 का उत्तर

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन

1646. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
सुश्री कंगना रनौत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड-गेज लाइन की वर्तमान स्थिति/प्रगति क्या है तथा भूमि अधिग्रहण, सुरंग संबंधी कार्य, पुल निर्माण, पटरी बिछाने और अन्य मुख्य अवसंरचना संबंधी कार्य क्या हैं और अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ख) भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी परियोजना के अंतर्गत अब तक योजनाकृत और पूरी हो चुकी सुरंगों, बड़े और छोटे पुलों, सड़क उपरिगामी पुलों (आरओबी), सड़क अधोगामी पुलों (आरयूबी) और अन्य संरचनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा विभिन्न पैकेज हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों और ईपीसी ठेकेदारों संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना की लागत में अपना पूरा प्रतिबद्ध अंशदान जमा कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की कुल लागत, आंवटित धनराशि कितनी है और अब तक जारी की गई धनराशि कितनी है, शेष धनराशि कितनी है और धनराशि की इस कमी से कार्यों के निष्पादन और ठेकेदारों को भुगतान किए जाने पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस लाइन को बेरी से आगे बिलासपुर-मनाली-लेह रणनीतिक रेल परियोजना से जोड़ने और बढ़ाने का कोई विचार है और यदि हाँ, तो सर्वेक्षण/डीपीआर की वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत और समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भूगर्भीय चुनौतियों, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं या अन्य प्रशासनिक कारणों से परियोजना को पूरा करने में कोई विलंब हुआ है और यदि

हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) रेल लाइन को पूरा करने, परीक्षण संचालन और साधारण जनता के उपयोग के लिए इसे शुरू करने की नियत की गई नई समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किलोमीटर) नई रेल लाइन परियोजना को लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की 25% भागीदारी और केंद्र सरकार की 75% भागीदारी है। इसके अलावा, भूमि की 70 करोड़ रुपए से अधिक की पूरी लागत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इस परियोजना को दो चरणों में शुरू किया गया है:

1. भानुपल्ली-बिलासपुर (52 किलोमीटर)
2. बिलासपुर-बेरी (11 किलोमीटर)

परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है:

खंड	स्थिति
भानुपल्ली - बिलासपुर (52 किलोमीटर)	232 हेक्टेयर भूमि में से 231 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। वन स्वीकृति प्राप्त की गई है अन्य कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है: सुरंगें: 16 में से 15 का कार्य पूरा किया जा चुका है बड़े पुल: 27 में से 10 का कार्य किया जा चुका है छोटे पुल : 49 में से 39 का कार्य पूरा किया

	जा चुका है ऊपरी सड़क पुल: 08 में से 06 का कार्य पूरा किया जा चुका है निचले सड़क पुल/एलएचएस: सभी 04 का कार्य पूरा किया जा चुका है रेलपथ जोड़ना: 52 टीकेएम में से 8 टीकेएम का कार्य पूरा किया जा चुका है
बिलासपुर - बेरी (11 किलोमीटर)	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

बिलासपुर से बेरी से आगे तक की भूमि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी जानी है। भूमि की अनुपलब्धता परियोजना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।

परियोजना पर अब तक किया गया कुल व्यय 8,237 करोड़ रुपए है। लागत साझाकरण व्यवस्था के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2,910 करोड़ रुपए दिए जाने थे। किन्तु, उनके द्वारा लागत के अपने हिस्से के रूप में केवल 847 करोड़ रुपए ही जमा किए गए हैं। इस प्रकार, 2,063 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ शेष हैं। लागत के अपने हिस्से की राशि जमा न करने से परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धता पूरा न करने के कारण इस परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है।

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल इसकी सफलता हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए किसी वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन (489 किलोमीटर)

रक्षा मंत्रालय द्वारा बिलासपुर-मनाली-लेह नई लाइन को सामरिक लाइन के रूप में चिह्नित किया गया है। सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह परियोजना हिमालय के कठिन भू-भाग से होकर गुजरती है, जो भूवैज्ञानिक चुनौतियों और कई समस्याओं से भरा हुआ है। परियोजना की कुल लंबाई 489 किलोमीटर है, जिसमें 270 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें शामिल हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,31,000 करोड़ है।

यह संरेखण बेरी, सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिसू, दारचा, केलांग, सरचू, पांग, रुमत्से, उपशी, खारू से होकर गुजरता है और लेह टर्मिनस पर समाप्त होता है, इस प्रकार यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है।

परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित होते हैं। चूंकि, परियोजनाओं को स्वीकृत करना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा विभिन्न हितधारकों द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन पर निर्भर करती है।

****